इकाई 29 समाजवादी विश्व-II

इकाई की रूपरेखा

29.0 उद्देश्य
29.1 प्रस्तावना
29.2 पृष्ठभूमि
29.3 नियोजन और औद्योगीकरण
- 29.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1929-33
- 29.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1933-37
- 29.3.3 नियोजित औद्योगीकरण के परिणाम
- 29.3.4 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1938-41

29.4 सामूहिक खेती
- 29.4.1 नई आर्थिक नीति में कृषि की कमजोरियां
- 29.4.2 अनाज का उत्पादन और विपणन
- 29.4.3 1927-28 का वसूली संकट
- 29.4.4 किसानों द्वारा सामूहिक खेती का विरोध
- 29.4.5 सामूहिकता की प्रकृति

29.5 आतंक और परिशोधन
- 29.5.1 चार मुकदमे
- 29.5.2 परिशोधन और साम्यवादी दल
- 29.5.3 परिशोधन और सेना
- 29.5.4 परिशोधन और सोवियत समाज

29.6 सारांश
29.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

29.0 उद्देश्य

पिछली इकाई के विवरण को इस इकाई में भी जारी रखा गया है, इसमें सोवियत रूस की चर्चा को आगे बढ़ाया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- 1930 के दशक में सोवियत रूस में प्रमुख राजनैतिक और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे,
- 1929 के बाद शुरु किए गए नियोजित औद्योगीकरण की प्रकृति का उल्लेख कर सकेंगे,
- कृषि की सामूहिकता और रूसी किसानों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाल सकेंगे, और
- 1930 के दशक के राजनैतिक कारकों से परिचित हो सकेंगे जिसके चलते आतंक और नरसंहार की शुरुआत हुई। (इस नरसंहार को राज्य ने परिशोधन अर्थात सफाया करना कहा)

29.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में रूसी क्रांति और क्रांति के बाद की प्रमुख घटनाओं की चर्चा की गई थी। उसमें आपने क्रांति के बाद स्थापित हुए साम्यवाद की जानकारी प्राप्त की। 1921 के आसपास युद्ध साम्यवाद का स्थान नई आर्थिक नीति ने ले लिया। 1928 के आसपास नई आर्थिक नीति के स्थान पर सोवियत रूस में उद्योग और कृषि का योजनाबद्ध ढंग से विकास शुरु हुआ। इस इकाई में रूसी अर्थव्यवस्था के योजनाबद्ध चरण की कहानी कही गई है। सबसे पहले योजनाबद्ध या नियोजित अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाया गया है। इसके

बाद 1930 के दशक की तीन प्रमुख घटनाओं की चर्चा की गई है; यह थी– नियोजित औद्योगीकरण, कृषीय सामूहिकता और 1930 के दशक का परिशोधन। इन तीनों ने सोवियत रूस के इतिहास को काफी प्रभावित किया।

29.2 पृष्ठभूमि

1926 ओर 1941 के बीच के कम समय में औद्योगीकरण का फैलाव तेजी से हुआ परंतु यह रूस में आधुनिक औद्योगीकरण की शुरुआत नहीं थी। 1890 के दशक में जार मंत्री एस.आई विट के प्रयास से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। प्रथम विश्वयुद्ध के पहले औद्योगीकरण में उछाल आया, शस्त्र निर्माण और अभियांत्रिकी उद्योगों का तेजी से विकास हुआ। परंतु युद्ध के दौरान इतना तेज और व्यापक विकास हुआ कि 1930 के दशक तक सोवियत रूस एक बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही से उबरने के बाद महाशक्ति के रूप में उभरने का यही आधार बना। 1926 से 1941 के दौरान हुआ सोवियत आर्थिक विकास दुनिया का पहला विस्तृत राज्य नियोजन था और इस प्रकार विश्व औद्योगीकरण के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

सोवियत सरकार में इस बात को लेकर कोई असहमति नहीं थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण आधुनिकीकरण और उद्योग के फैलाव से किया जा सकता है। इससे दुनिया के एकमात्र समाजवादी देश (1949 तक) को विरोधी पूंजीवादी दुनिया का सामना करने की ताकत मिलेगी। इस बात पर भी कोई असहमति नहीं थी कि औद्योगीकरण कृषि के आधुनिकीकरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकता था। कृषि की उत्पादकता बढ़ाए बिना औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या को एक बेहतर जीवन स्तर देना संभव नहीं था और प्रौद्योगिकी तथा मशीन के आयात के भुगतान के लिए अनाज का निर्यात जरूरी था तथा युद्ध और अकाल के समय के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार सुरक्षित रखना भी जरूरी था।

सोवियत बोलशेविकों जैसे मार्क्सवादी सदैव अर्थव्यवस्था के 'नियोजन' में विश्वास रखते थे। मार्क्स ने कहा था कि एक समाजवादी समाज बाजार की ताकतों के निरंकुश नियंत्रण से या पूंजीपति वर्ग के अधिकतम मुनाफा कमाने के आत्म हित नियंत्रण से मुक्त होगा। इसके स्थान पर समाजवादी समाज लोगों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों पर सीधा नियंत्रण रखेगा और योजनाबद्ध ढंग से उत्पादन करेगा।

29.3 नियोजन और औद्योगीकरण

1920 से ही दस से पन्द्रह साल की दीर्घवधि योजना का विचार पनप रहा था। 1925 से वार्षिक नियंत्रण और अनुमान के लिए वार्षिक नियोजन पूर्वानुमान तैयार किया जा रहा था। 1926 से राज्य योजना आयोग (गौसप्लान) और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था परिषद (VSNKH) ने भावी पंचवर्षीय योजना के कई प्रारूप बना डाले थे। इसका दोहरा महत्व था। इससे औद्योगीकरण के प्रति प्रतिबद्धता की शुरुआत हुई और एक विस्तृत योजना के द्वारा राज्य के नेतृत्व में विकास हुआ। दूसरे, इसे कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षाकृत कम समय की योजना बनाई गई।

1926 तक अधिकांश सोवियत उद्योग 1913 के उत्पादन स्तर तक पहुंच गए और कुछ उद्योगों ने यह स्तर भी पार कर लिया। इसके बाद सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में निम्नलिखित पक्षों पर बल दिया :

- समाजवादी ढर्रे पर तीव्र औद्योगीकरण, और
- ऐसी औद्योगीकरण पद्धति जिसमें बड़े पैमाने के उद्योग उत्पादन तंत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर वर्चस्व हो।

सोवियत रूस में समाजवाद का निर्माण हो रहा था और वह चारो ओर से शत्रुतापूर्ण पूंजीवादी विश्व से घिरा हुआ था; इसलिए सोवियत उद्योग का इस अर्थ में आत्म निर्भर होना जरूरी था कि किसी बड़े उत्पाद के लिए उसे पूंजीवादी देशों पर आश्रित न रहना पड़े। कम से कम समय में पूंजीवादी देशों से आगे बढ़ना एक प्रमुख उद्देश्य था।

इसके लिए पूंजी, उपकरण, रसायनों और अन्य विकसित उत्पादों के उत्पादन की क्षमता हासिल करना आवश्यक था जिसका जार युग उद्योग में अभाव था। आत्मनिर्भरता के लिए भी सोवियत उद्योग को अत्यधिक विकसित प्रौद्योगिकी को हासिल करना अनिवार्य था। इस बात पर भी सहमति थी कि उत्तर पश्चिम, मध्य यूरोपीय रूस और यूक्रेन जैसे आधुनिक उद्योग के परम्परागत केंद्र में नए कारखाने नहीं लगाए जाएंगे बल्कि इनकी स्थापना उराल और साइबेरिया तथा पिछड़े मध्य एशिया में की जाएगी। प्रतिरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोहे और इस्पात निर्माण, अभियांत्रिकी और अस्त्र बनाने वाले उद्योगों की स्थापना सोवियत रूस के उन क्षेत्रों में की गई जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता था।

29.3.1 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1929-33

चूंकि 1928 औद्योगिक वृद्धि के लिए एक सफल वर्ष था अत: पुराने योजना लक्ष्यों को संशोधित कर आगे बढ़ाया गया। किसी को भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य पद्धति को समझने की सांख्यिकी सूचना या सैद्धांतिक समझ नहीं थी। जैसे-जैसे नई आर्थिक नीति के तहत बाजार अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वृद्धि की दर बढ़ने लगी वैसे-वैसे प्रमुख सोवियत नेता स्टालिन अधीर होते गए और सतर्क नियोजन का स्थान राजनीति ने ले लिया। अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं की देखभाल कर योजनाबद्ध ढंग से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के स्थान पर एक 'आदेशात्मक' अर्थव्यवस्था का आगमन हुआ जो राजनैतिक आदेशों और सरकार की प्राथमिकताओं से निर्देशित होती थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में लोहे और इस्पात पर अधिक ध्यान दिया गया परंतु ट्रैक्टर्स संयंत्रों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई। विदेश से मशीन आयात की निर्भरता को समाप्त करने के लिए मशीन और औजार उद्योग का तेजी से विकास हुआ। स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत नेतृत्व कुछ पूर्वाग्रहों से युक्त था जिसका प्रभाव नियोजन पर पड़ा। उनका मानना था कि बड़े-बड़े औद्योगिक परिसरों के निर्माण से ही औद्योगिक विकास हो सकता था। इसमें ऐसे बड़े औद्योगिक परिसरों के निर्माण की मांग की गई जिन्हें चलाने या बनाने के लिए संसाधन मौजूद नहीं था। परिणामस्वरूप इसे बनाने में ज्यादा समय लगा और बार-बार काम रुका तथा कुछ काम अधूरे भी छूट गए। आकार के साथ-साथ सब कुछ जल्दी में भी करने का आग्रह था। इसलिए इस समय तेज काम करने का नारा दिया गया। इसके लिए 1929 के मध्य में औपचारिक रूप से प्रथम पंचवर्षीय योजना अपनाई गई; इसकी शुरुआत अक्टूबर 1928 से मानी गई और अन्तत: जनवरी 1933 में इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना पांच वर्षों में ही नहीं बल्कि सवा चार वर्षों में ही सम्पन्न हो गई।

चित्र 1: जोज़ेफ स्टालिन

उत्पादन की मात्रा के रूप में योजना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। योजना में उत्पादन बढ़ाने के लिए वास्तविक सामग्री संसाधनों की उपलब्धता का बहुत ही अस्पष्ट संकेत दिया जाता था। उद्योग से यह उम्मीद की जाती थी कि वह केवल योजना के लक्ष्यों को ही न छुएं बल्कि उससे आगे भी बढ़ जाए। योजना का उद्देश्य संसाधन आवंटित करना या संतुलित मांगों की पूर्ति करना नहीं था बल्कि अर्थव्यवस्था को खींच-खींच कर आगे बढ़ाना था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में तेजी से कमी आई और नई मशीने महंगी होने के बावजूद काफी खराब किस्म की थीं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के मिले जुले परिणाम सामने आए। हालांकि धातु उत्पादन बढ़ाने के लिए सबकुछ त्याग दिया गया परंतु कोयला, तेल, कच्चा लोहा और लौह पिंड का उत्पादन उम्मीद से काफी कम हुआ। मशीनरी और धातु कर्म में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा उत्पादन हुआ परंतु ऐसा भी अंशत: आंकड़ों के हेर-फेर से हुआ। 1940 में इस्पात उत्पादन, 1951 में बिजली उत्पादन और 1955 में तेल उत्पादन का लक्ष्य पूरा हुआ। भारी उद्योग में तेजी से विकास के लिए उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि और थोड़े समय के लिए सैन्य शक्ति की भी बलि दे दी गई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य ने संभवत: आपूर्ति और वितरण के संगठन का सर्वाधिक कठिन कार्य किया। एक दशक पूर्व गृह युद्ध के दौरान ऐसा करने का असफल प्रयत्न किया गया था, इसलिए राज्य ने शहरी अर्थव्यवस्था, वितरण और व्यापार का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इस बार 1980 के दशक तक यह स्थिति बनी रही। 1920 के दशक के अंत से निजी उत्पादन और व्यापार में कटौती की जाने लगी। नई आर्थिक योजना के लोगों (निजी व्यापारियों) के खिलाफ तेजी से कार्यवाई की गई। उनके खिलाफ

अखबारों में दुष्प्रचार किया गया, कानूनी और वित्तीय स्तर पर उन्हें परेशान किया गया और 1928-29 में 'अटकलबाजी' के आधार पर कई निजी उद्यमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 के दशक के आरंभ में छोटे कारीगरों और दुकानदारों से भी उनका व्यापार छीन लिया गया था या उन्हें राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों में शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। अभी तक व्यापार और वितरण का वैकल्पिक ढांचा तैयार नहीं हुआ था। कृषि की सामूहिकता के साथ ही नई आर्थिक नीति की मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य ओर निजी क्षेत्र मिलजुल काम करते थे पूर्णतया समाप्त हो गई।

29.3.2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1933-37

फरवरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इसके तीन निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार थे :

- दृढ़ीकरण
- तकनीक पर अधिकार, और
- जीवन स्तर सुधारना

इस योजना में तर्कसंगत नियोजन के सिद्धांत को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया। अधिक संतुलित और वास्तविक उत्पादक लक्ष्य रखे गए। उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना और निपुणता हासिल करना मुख्य उद्देश्य हो गया।

इस योजना में उत्पादक माल की अपेक्षा उपभोक्ता माल में अधिक निवेश और उत्पादन वृद्धि पर बल दिया गया। नगद मजदूरी में वृद्धि और चीजों की कीमतों में कमी आने से शहरों में रहने वाले मजदूरों की मजदूरी में वास्तविक बढ़ोत्तरी की उम्मीद की गई।

दूसरी योजना के दौरान बड़ी संख्या में औद्योगिक उद्यम स्थापित किए गए। इसका मतलब यह हुआ कि 1927 तक 80% औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन नए या पूरी तरह पुनर्निर्मित उद्यमों में होने लगा। इस योजना के दौरान भारी उद्योगों के उद्देश्य लगभग पूरे कर लिए गए और मशीनों तथा बिजली के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई।

हालांकि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन उम्मीद से कम बढ़ा और 1928 के मुकाबले 1937 में जरूरी घरेलू वस्तुओं का प्रति व्यक्ति उपभोग कम रहा। मैग्निटोगोर्सक, कुजनेस्क और जापोरोझे में धातुकर्म का कार्य पूर्ण होने से सोवियत रूस की विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम हो गई, भुगतान संतुलन का भार कम हुआ और पुराने ॠणों को चुकाने में सहूलियत हुई। 1937 तक आधारभूत मशीनें और प्रतिरक्षा सामान सोवियत रूस में बनाए जाने लगे। इस योजना के दौरान मध्य एशिया और कजाकिस्तान में पिछड़े राष्ट्रीय गणतंत्रों को विकसित करने का प्रयत्न किया गया। हालांकि सीमित संसाधनों के उपयोग को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था।

29.3.3 नियोजित औद्योगीकरण के परिणाम

1928 के बाद के दशक में विश्व अर्थव्यवस्था के इतिहास में सोवियत उद्योगों का विकास अभूतपूर्व दर और गति से हुआ। सोवियत सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1928 की तुलना में 1937 में औद्योगिक उत्पादन 446 % बढ़ गया, संकुचित पश्चिमी आकलन के अनुसार 239 % की वृद्धि हुई। इसी प्रकार सोवियत आंकड़ों के अनुसार वृद्धि दर 18 % और पश्चिमी आंकड़ों के अनुसार यह वृद्धि 10.5 % थी।

सोवियत सरकारी आंकड़ों के अनुसार विश्व उत्पादन में सोवियत रूस का हिस्सा जहां 1913 में 2.6 % और 1929 में 3.7 % था वहीं 1937 में यह बढ़कर 13.7 % हो गया। सोवियत रूस एक तरफ ऊंचाइयों को छू रहा था जबकि पश्चिमी देश भयंकर मंदी और व्यापक बेरोजगारी से गुजर रहे थे। 1928 में सोवियत रूस का औद्योगिक उत्पादन जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन जैसे द्वितीय श्रेणी के पूंजीवादी देशों के स्तर का था। 1937 तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका इससे आगे रह गया। तब तक प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के मुकाबले सोवियत संघ की उत्पादन शक्ति दोगुनी हो चुकी थी। सोवियत उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग में परिणत हो गया: 1913 में सोवियत औद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा लघु उद्योगों में होता था जबकि 1937

तक यह अनुपात गिरकर मात्र 6 % रह गया। पश्चिम से मशीनों और जानकारियों का भारी मात्रा में निर्यात कर प्रमुख नए उद्योगों की स्थापना की गई। 1937 तक आते-आते सोवियत संघ बड़ी मात्रा में लोहा और इस्पात तथा बिजली के उपकरण, ट्रैक्टर, फसल कटाई के उपकरण, टैंक और हवाई जहाज के साथ-साथ सभी प्रकार के मशीन उपकरण बनाने लगा; और सभी उद्योग में प्रौद्योगिकी का स्तर ऊपर उठा। श्रम उत्पादकता (कार्यरत प्रति व्यक्ति उत्पादन) में प्रतिवर्ष औसतन 6 % की वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी में किसी भी समय ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका में इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हुई थी।

यूराल और उसके आगे के क्षेत्र में नए औद्योगिक परिसरों का निर्माण हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के गहरे संकट के समय यही सोवियत शस्त्र उद्योग का आधार बना जबकि अधिकांश यूरोपीय सोवियत संघ पर दुश्मनों कर कब्जा हो गया था। कुछ अति पिछड़े गणतंत्रों में आधुनिक उद्योगों की भी स्थापना की गई।

29.3.4 तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1938-41

1938 और 1941 के बीच जर्मनों ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का साढ़े तीन वर्ष इसी में खप गया। 1 जून 1941 में द्वितीय विश्वयुद्ध से योजना में बाधा पड़ी और यह कभी पूरा नहीं हो पाया। इस समय भी पांच वर्षों के दौरान प्रभावी प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया : औद्योगिक उत्पादन में 92, इस्पात में 58, मशीन और अभियांत्रिकी में 129। एक बार फिर उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई।

बोध प्रश्न 1

1) नियोजित औद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं ? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं ने रूसी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया ? दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

29.4 सामूहिक खेती

पिछले भाग में औद्योगीकरण पर बातचीत करने के कम में हमने देखा कि सोवियत नेतृत्व ने सफलतापूर्वक अपने देश को विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिणत कर दिया। हालांकि कृषि में प्रमुख बदलाव लाए बिना औद्योगीकरण संभव नहीं था। गृहयुद्ध के बाद उत्पाद में हुई पर्याप्त वृद्धि के बावजूद प्रति हेक्टेयर उत्पादन और श्रम उत्पादकता दोनों ही दृष्टियों से सोवियत कृषि किसी भी प्रमुख यूरोपीय देश से बहुत पिछड़ा हुआ था। अधिकांश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर राज्य ने उद्योग के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी परंतु कृषि क्षेत्र में निजी कृषक खेतों की मौजूदगी के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन और विपणन निर्णयों पर राज्य का नियंत्रण नहीं था और वे केंद्रीय नियोजन के दायरे से बाहर थीं।

बोलशेविकों का मानना था कि पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बड़े खेतों में अधिक उत्पादन संभव होगा क्योंकि इनमें मशीनों और उर्वरकों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से किया जा सकता था। इनसे औद्योगीकरण के लिए कृषि अधिशेष का निर्माण होगा। इसके अलावा उत्पादन संसाधनों को एक बड़े खेत में लगाने से किसानों के बीच धन की असमानता भी दूर होगी। बोलशेविकों का मानना था कि किसानों को सामूहिक और समाजवादी खेती के लिए राजी करने में काफी वक्त लगेगा और यह दुरूह प्रक्रिया होगी। अपने एक लेख 'सहयोग की ओर' में लेनिन ने लिखा था कि सरकार को किसानों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करना चाहिए कि वे अपने निजी खेत छोड़ दें और सामूहिक खेतों में मिल जुलकर काम करें। इसके लिए किसानों को आधुनिक उपकरण, ऋण और कृषि संबंधी सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी।

नई आर्थिक नीति में विकसित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बल नहीं दिया गया जिससे कि किसानों को सामूहिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जब तक सोवियत रूस में ट्रैक्टर आए अधिकांश बोलशेविकों का मानना था कि समाजवादी कृषि की तैयारी के लिए कई कदम उठाने होंगे। किसानों को धीरे-धीरे सामूहिक खेती की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए पहले उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने, कृषि उत्पादों के विपणन और आपूर्ति के लिए सहकारी समितियां बनानी होगी और मशीन, बीज, भूमि सुधार, निर्माण के लिए सहकारी समितियों को ऋण उपलब्ध कराना होगा और अंत में उन्हें सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करना होगा।

1920 के दशक में कृषिशास्त्रियों और भूमि चकबंदी विशेषज्ञों को कुछ किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रेरित करने में थोड़ी बहुत सफलता मिली। परंतु अभी काफी कम किसान इस प्रकार की खेती के लिए राजी थे। यह सोचकर कि सहकारी समितियों के निर्माण से किसानों में सामूहिकता की भावना बढ़ेगी, सोवियत राज्य ने सहकारी समितियों को आसान ऋण, कर छूट और दुर्लभ उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति में प्राथमिकता देने का वादा किया। परंतु सहकारी समितियां भी किसानों को आकर्षित करने में बहुत सफल नहीं रहीं।

ग्रामीण पूंजीवाद के प्रसार से किसानों के बीच बढ़ता अंतर सोवियत नेतृत्व के लिए चिंता का विषय था। ग्रामीण पूंजीवाद से केवल अमीर कृषकों या *कुलक* को ही फायदा हो रहा था जिसकी कीमत पूरे कृषक समुदाय को चुकानी पड़ रही थी। तीन तरीकों से किसानों के बीच अंतर बढ़ रहा था, जैसे पट्टे पर जमीन देना; ऋण, पशु, उपकरण और मशीन की उपलब्धता; और मजदूरों को मजदूरी पर रखना। कुलक उन्हें कहा गया जो मजदूर रखते थे, खरीदकर या पट्टे पर जमीन प्राप्त करते थे, जिनके पास बड़ी मिल्कियत थी और जो कृषि के उत्पादन के साधनों को पट्टे पर उठाया करते थे तथा जिनकी वाणिज्यिक और वित्तीय कारोबार से आमदनी थी। परंतु कभी भी कुलक की स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

29.4.1 नई आर्थिक नीति में कृषि की कमजोरियां

नई आर्थिक नीति के दौरान किसानों के खेती करने का तरीका और प्रौद्योगिकी काफी पिछड़ी हुई थी। 1927 में, खेती योग्य जमीन का 88 प्रतिशत हिस्सा छोटे-छोटे खेतों में विभक्त था और पांच प्रतिशत से कम खेतों की पूरी तरह या आंशिक रूप से घेराबंदी की गई थी। खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे होने के कारण खेती की आधुनिक तकनीकों और बेहतर उपकरणों का उपयोग संभव नहीं था। पूरे साल में खेतों में दो फसलें उगाई जाती थी; और पहले चक्र में शरत ऋतु में राई, गेहूं तथा दूसरे चक्र में वसंत ऋतु में गेहूं या अन्य फसल बोई जाती थी और तीसरे चक्र में खेत परती छोड़ दिया जाता था; इसे तीन चक्रीय खेती व्यवस्था के रूप में जाना जाता था और सोवियत संघ में यही पद्धति सबसे ज्यादा प्रचलित थी। इसके अलावा इससे भी पुरानी अलग-अलग खेतों पर खेती करने या स्थानांतरित खेती प्रथा भी मौजूद थी। इसके परिणामस्वरूप एक तिहाई हिस्सा हमेशा परती पड़ा रहता था।

सरकार जल्द से जल्द प्रौद्योगिकी में सुधार लाना चाहती थी परंतु यह इतना आसान नहीं था। 1927 में रूसी संघ के लगभग एक चौथाई किसानों के पास घोड़ा या बैल नहीं था और एक तिहाई किसानों के पास खेत जोतने के उपकरण नहीं थे। अधिकांश किसानों के पास बिना घोड़े के उपयोग किए जानेवाले उपकरण थे; कई किसानों के पास यह भी नहीं था पर वे भी इसी प्रकार के औजार का इस्तेमाल करते थे। मशीनों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर अनाज उत्पादन करने वाले प्रमुख देहाती क्षेत्रों में ही होता था।

29.4.2 अनाज का उत्पादन और विपणन

हालांकि 1920 के दशक तक अनाज का उत्पादन युद्ध पूर्व स्तर तक पहुंच गया था परंतु 1920 के दशक में प्रथम विश्व युद्ध के पहले की तुलना में अनाज का विपणन काफी कम हुआ था। ऐसा अंशतः गांव की जनसंख्या में वृद्धि के कारण हुआ 1913 और 1926 के बीच 60 लाख आबादी बढ़ी जबकि 1913 की तुलना में इस समय प्रति व्यक्ति अनाज उत्पादन में 16 प्रतिशत की कमी आई।

चित्र– 2 यूक्रेन में सामूहिक खेती का एक दृश्य

एक प्रमुख समस्या यह थी कि कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक से अधिक बाजार थे। अन्न और अन्य फसलों के बाजारों में राज्य और सहकारी प्रयत्नों का हिस्सा काफी कम था और निजी बाजार में उत्पादकों को लाभ के कई विकल्प उपलब्ध थे। राज्य खरीद अभिकरणों की अपेक्षा किसानों के लिए निजी बाजार में अनाज बेचना ज्यादा लाभप्रद था क्योंकि यहां ऊंची कीमतें मिलती थीं। निजी व्यापारियों से किसानों को अपनी ओर खींचना राज्य की एक बहुत बड़ी समस्या थी।

व्यापार की शर्तें या औद्योगिक खुदरा मूल्यों और राज्य के कृषि खरीद मूल्य के बीच का संबंध युद्ध पूर्व समय की अपेक्षा किसानों के लिए कम अनुकूल था। अपने उत्पादों के लिए प्रतिकूल मूल्य अनुपात के अलावा युद्ध पूर्व समय की अपेक्षा किसानों की औद्योगिक वस्तुओं तक पहुंच भी कम हो गई। 1920 के पूरे दशक में औद्योगिक वस्तुएं महंगी, खराब कोटि की और दुर्लभ हो गईं।

राज्य के अनाज का खरीद मूल्य (जागातोवकी) इतना कम होता था कि इससे अक्सर उत्पादन की लागत भी नहीं निकल पाती थी। पशुधन उत्पाद और औद्योगिक फसलों का मूल्य किसानों के अधिक अनुकूल था और इससे अनाज वितरण को धक्का पहुंचा।

1917-20 की कृषि क्रांति के बाद गांवों में सामाजिक और आर्थिक संगठनों में हुए परिवर्तन से भी कृषि विपणन में गिरावट आई। बड़ी निजी सम्पदाओं के पुनर्विभाजन से वे कृषि इकाइयां समाप्त हो गईं जो अधिक बाजारोन्मुख थीं।

29.4.3 1927-28 का वसूली संकट

1927 की खरीफ की फसल अच्छी होने के बावजूद किसान अपेक्षाकृत कम अनाज बाजार में ले गए और सरकार इतना अनाज न खरीद सकी जिससे शहर के लोगों और सेना का भरणपोषण तथा मशीनों के आयात के लिए अनाज का निर्यात किया जा सके। यदि राज्य निजी बाजारों के मूल्यों का मुकाबला करने के लिए

अनाज का खरीद मूल्य बढ़ाता तो औद्योगिक विकास के लिए आवंटित राशि में कटौती करनी पड़ती।

1927-28 के दौरान औद्योगिक निवेश में हुई तीव्र वृद्धि अक्टूबर 1927 के बाद से होने वाले अनाज संकट का प्रमुख कारण था। भारी उद्योग में निवेश किए जाने के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की और भी कमी पड़ गई; और अनाज का राज्य खरीद मूल्य कम होने के कारण उन्हें खरीदना और भी महंगा पड़ता था।

उत्पाद की इस कमी के जवाब में किसानों ने 'उत्पादन हड़ताल' कर दी और राज्य द्वारा निर्धारित मूल्यों पर सरकार को अनाज बेचने से मना कर दिया। किसानों ने या तो निजी व्यापारियों को ऊंचे दामों पर अनाज बेचा या कर चुकाने के लिए महंगी औद्योगिक फसलों या पशु उत्पादों की बिक्री की।

दूसरे शब्दों में, 1927 का संकट इस अर्थ में कोई आर्थिक संकट नहीं था जिसमें बाजार तंत्र बिखर गया हो या उत्पादकता क्षमता कम हो गई हो। यह इस बात से स्पष्ट है कि फसल का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचा जाता था पर अक्सर वे निजी व्यापारियों के पास जाते थे। किसान अधिशेष उत्पादन के लिए तैयार थे और उनके पास इसकी क्षमता भी थी परंतु वे चाहते थे कि अपने इस अधिशेष से वे औद्योगिक वस्तुएं खरीद सकें।

दिसम्बर 1927 में स्टालिन ने कहा कि किसानों के छोटे-छोटे और बिखरे खेतों को एकत्रित करने का काम धीरे-धीरे शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए बल्कि समझाने बुझाने का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगले महीने जनवरी 1928 में उन्होंने कहा कि "हम कुलक की सनक पर अपने उद्योग को आश्रित नहीं कर सकते; (सामूहिक खेती) पूरे जोर शोर से लागू करनी होगी......ताकि तीन या चार वर्षों (1931 या 1932 तक) के भीतर वे राज्य के अनाज की जरूरत के कम से कम एक तिहाई हिस्से की आपूर्ति कर सकें।''

दल नेतृत्व ने किसानों से बातचीत करने की अपेक्षा टकराव का रास्ता अपनाया। 1928 के आरंभ में बाजार बंद कर दिए गए और किसानों तथा व्यापारियों से अनाज जब्त कर लिया गया। जिन लोगों ने अनाज छिपाने या दबाने और आपूर्ति करने में आनाकानी की उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य ने बड़ी मात्रा में अनाज वसूली की।

1928 की गर्मी में पार्टी ने पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक तेजी से ज्यादा से ज्यादा अनाज वसूलने का अभियान छेड़ा। नवंबर में प्राधिकारियों ने पांच महीने के भीतर प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सामूहिक खेती लागू करने की घोषणा की। 1928 में प्रमुख अनाज उत्पादक क्षेत्रों यूक्रेन और उत्तरी काकेशस में पैदावार अच्छी नहीं हुई। देश के दूरस्थ पूर्वी भागों (वोल्गा क्षेत्रों, कजाकिस्तान, यूराल और साइबेरिया) में पैदावार सर्वोत्तम हुई परंतु यहां राज्य वसूली तंत्र सबसे कमजोर था, सूचना, संचार आदि अधिसंरचना अल्प विकसित थी जो जाड़े में ज्यादा ही धीमी हो जाती थी। उत्पादित वस्तुओं की कमी से संकट और भी गहरा हो गया। अनाजों के विपणन में तेजी से गिरावट आई और राज्य अभिकरण अनाज वसूली में असफल रहे। राइ, (एक प्रकार का अनाज जिसका उत्पादन यूरोप में होता है) गेहूं और खाद्यान्नों की कम वसूली के कारण राज्य को अनाज के निर्यात में कटौती करनी पड़ी और शांति काल में भी राशन व्यवस्था पुनः लागू की गई।

सोवियत नेताओं के सामने दो विकल्प मौजूद थे। वे नई आर्थिक नीति, संतुलित औद्योगीकरण, धीरे-धीरे सामूहीकरण और किसानों को बाजार में अधिक अनाज लाने के लिए कृषि आपूर्ति मूल्य का समायोजन का रास्ता अपना सकते थे; बुखारिन जैसे नेताओं ने इसी प्रकार की नीति की वकालत की थी। इसके अलावा वे जोर जबरदस्ती से सामूहीकरण और औद्योगीकरण की नीति अपना सकते थे। स्टालिन ने दूसरा विकल्प चुना।

सामूहीकरण नीति के अन्तर्गत गांव और जिलों में बड़े-बड़े खेतों का निर्माण करना था। 1929 के वसंत में व्यापक पैमाने पर सामूहीकरण अपनाने के लिए कुछ जिलों को चुना गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग सभी घरों को सामूहीकृत किया गया। जुलाई के आरंभ तक ऐसे लगभग 11 जिलों को चुना गया।

जिस समय व्यापक पैमाने पर सामूहीकरण किया गया उसके लिए कोई लम्बी चौड़ी योजना नहीं बनाई गई। यहां तक कि [illegible] में भी कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया गया। यह मान

लिया गया था कि 1934 में चार में से तीन किसानों के खेत अभी भी निजी मिल्कियत में रहेंगे और अनाज की मंडी में आधे से ज्यादा अनाज की पूर्ति यही करेंगे। सामूहिकता आरोपित करने का निर्णय तीव्रता मे लिया गया। यह न तो पार्टी का निर्णय था और न ही इसमें कानूनी सलाह ली गई थी। [illegible] में कुलक को समाप्त करना था और पूरे ग्रामीण इलाकों में सामूहीकरण का अभियान चलाना था ताकि गांवों को कुलक विहीन कर दिया जाए। अनाज वसूली अभियान और किसानों को [illegible] कोलखोज (सामूहिक भू क्षेत्र) में मिलाने का कार्यक्रम एक साथ मिला दिया गया।

इस सामूहिक कार्यकलाप के बारे में कोई ढांचा या संगठन नहीं बनाया गया; यह भी नहीं तय किया गया कि निर्णय किस प्रकार लिया जाएगा और सदस्यों को भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। सात सप्ताहों के भीतर फरवरी 1930 तक लगभग आधे किसान सामूहीकरण अभियान की लपेट में आ [illegible]।

29.4.4 किसानों द्वारा सामूहिक खेती का विरोध

किसानों पर जबरदस्ती सामूहिकता थोप दी गई जिसका किसानों ने जमकर मूक और सशस्त्र विद्रोह किया। किसानों ने जमकर शासन का विरोध किया और चारों ओर हजारों किसानों ने जन प्रदर्शन किए। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियां हुईं जिसमें लोगों को मारा पीटा गया, हत्याएं की गईं, आगजनी और लूटपाट मचाई गई। कुल मिलाकर किसानों का यह विद्रोह स्थानीय और मुखर था परंतु इसमें शस्त्रों का उपयोग अपेक्षाकृत कम हुआ था। समृद्ध किसानों का प्रतिरोध सबसे ज्यादा मुखर था परंतु यह स्पष्ट था कि किसानों का हर वर्ग इससे प्रभावित हुआ था और सामूहीकरण के विरोध में सारे किसान शामिल थे।

कोलखोज (सामूहिक भू क्षेत्र) को अपने पशु सौंपने की अपेक्षा कई किसानों ने अपने पशुओं की हत्या कर दी (16 जनवरी 1930 की राज्याज्ञा के द्वारा इस प्रकार की हत्याओं पर प्रतिबंध लगाया गया था और इस अपराध के लिए सम्पत्ति जब्त की जा सकती थी और कारावास या देश निकाला की सजा हो सकती थी) या नजदीक के शहर में जाकर उसे बेच दिया। इसके परिणामस्वरूप 1928 के मुकाबले 1933 में एक तिहाई भेड़, आधे घोड़े और सूअर तथा 54 प्रतिशत कम जानवर रह गए।

कृषि अर्थव्यवस्था पर आक्रमण करने के साथ-साथ परम्परागत कृषक संस्कृति के केंद्र में कट्टरपंथी चर्च के खिलाफ भी तेज अभियान चलाया गया। सभी ऐतिहासिक चर्चों को ध्वस्त कर दिया गया और कई पुजारियों को बंदी बना लिया गया। मठ बंद कर दिए गए। इनमें से अधिकांश में नमूने के तौर पर कृषि सहकारी समितियां चलाई गईं और हजारों पुजारियों और पुजारिनों को साइबेरिया भेज दिया गया। 1930 के अंत तक लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण चर्च बन्द हो चुके थे। कुलक विरोधी अभियान के द्वारा लगभग 1,000,000 किसान परिवार (औसतन प्रति गांव एक परिवार) या लगभग 50 से 60 लाख लोग अपनी जमीन और घर से हाथ धो बैठे।

रूस के देहातों में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था जिसके कई रूप थे। बचे हुए पशुधन अस्त व्यस्त हालत में थे और वसंत में होने वाली खेती बीज के अभाव में नहीं हो पा रही थी। मार्च 1930 में स्टालिन ने अपने एक लेख ''डिजी विट सक्सेस'' में उन्होंने इस ज्यादती का आरोप अपने अधिकारियों पर लगाया। उसने थोड़े दिन के लिए सामूहीकरण अभियान बंद कर दिया ओर आदेश दिया कि कुलकों को छोड़कर [illegible] के एकत्र किए पशु उनके मालिकों को लौटा दिया जाए और इस प्रकार कृषक बाजार को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयत्न खत्म हुआ। किसानों ने यह समझा कि अनिवार्य सामूहीकरण वापस ले लिया गया है और अधिकांश किसान तीव्रता से सामूहीकरण से अलग हो गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार [illegible] मार्च और । जून 1930 के बीच सोवियत रूस में सामूहिकृत कृषक परिवारों का प्रतिशत 56 से [illegible] तक पहुंच गया और अगस्त में यह 21.4 रह गया।

कोलखोज के एक नए मॉडल अधिनियम में इसके सदस्यों को एक गाय, भेड़ [illegible] रखने और अपने छोटे व्यक्तिगत खेत पर खुद काम करने के लिए कृषि औजार रखने की रियायत दी गई। इन छोटे निजी खेतों से किसानों को आमदनी होती थी, उनका खाना-पीना चलता था और अनाज बेचकर वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करते थे।

सामूहीकरण अभियान थोड़े दिनों के लिए ही शिथिल किया गया था। 1930 में मौसम अनुकूल और फसल बेजोड़ रही। जैसे ही राज्य के भंडारों में अनाज भरा वैसे ही इस बार स्पष्ट निर्देशों के साथ सामूहीकरण

अभियान वापस शुरू कर दिया गया। कोलखोज संगठनकर्ताओं और अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए दस हजार साम्यवादी और शहरी मजदूरों को गांवों में भेजा गया। ग्रामीण जनता से जबरदस्ती की गई और उन पर मनमाने ढंग से कर लादा गया ताकि वह सामूहीकरण में लौट जाएं। 1937 तक कुल फसल क्षेत्र का 86 प्रतिशत कोलखोजों के अधीन आ गया था, 89 प्रतिशत अनाज सामूहिक खेतों में पैदा हुआ और सरकार ने 87 प्रतिशत वसूली इन्हीं खेतों से की।

29.4.5 सामूहिकता की प्रकृति

सामूहीकरण को कभी-कभी 'दूसरी क्रांति' भी कहा जाता है क्योंकि इसने किसानों के जीवन को बोलशेविक क्रांति से भी ज्यादा प्रभावित किया। किसानों ने इसको अपने आप स्वीकार नहीं किया बल्कि इसे शहरी और सर्वहारा दल के द्वारा जबरदस्ती लादा गया; कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऊपर से आरोपित क्रांति थी। सामूहीकरण के पहले और बाद किसानों की स्थिति में प्रमुख और आधारभूत अन्तर यह था कि एक सामूहिक किसान का सामूहिक खेती से उगाए अनाज और नगदी फसल पर कोई अधिकार नहीं था। अधिकांश सामूहिक खेत पूर्ववर्ती कम्युन के समान थे और किसानों की हालत लगभग कृषि दासों जैसी हो गई थी।

किसानों को खेत छोड़कर जाने का अधिकार नही था; कृषकों के मन में यह बात घर करने लगी कि यह सामूहीकरण कृषिदास प्रथा का ही नया रूप था। किसान व्यंग्य किया करते थे कि अखिल संघ साम्यवादी दल (रूसी भाषा में वी के पी) "कृषि दास व्यवस्था" (वतोरो क्रेपोस्तनो प्रावो) का ही दूसरा नाम है।

सामूहीकरण के द्वारा राज्य ने अनाज, आलू और सब्जियों की वसूली बढ़ाई; इससे उद्योगों को कृषक मजदूर मिले, परंतु इससे पशुधन की हानि हुई; कृषि का उत्पादन जारी रहा और ग्रामीण शहरी लोगों का जीवन स्तर कायम रहा। परंतु इसमें कृषि में किए गए विस्तार से लोगों की बढ़ती मांग पूरी नहीं की जा सकी और इस अर्थ में यह असफल रहा।

अनाज उत्पादन, उपज और राज्य वसूली

वर्ष	अनाज उत्पादन मिलियन टन	उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर	वसूली
1909-13	72.5	6.9	–
1928-32	73.6	7.5	18.1
1933-37	72.9	7.1	27.5
1938-40	77.9	7.7	32.1

स्रोत : मोशे लेविन, **द मेकिंग ऑफ द सोवियत सिस्टम: एस्सेज इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इन्टरवार रशिया**, लंदन: मेथ्यून, 1985, टेबुल 6.2 पृष्ठ 167

बोध प्रश्न 2

1) कृषि सामूहिकता का समावेश किस प्रकार किया गया। दस पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

2) सामूहीकरण अभियान की किसानों पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? पचास शब्दों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

29.5 आतंक और परिशोधन

सामूहीकरण और औद्योगीकरण के जबरदस्ती लागू करने से सोवियत जनता के जीवन में कोई सुधार नहीं आया बल्कि ऊपर से आरोपित क्रांति धीरे-धीरे आतंक के राज्य में परिणत हो गई। यह केवल किसानों और पूंजीवाद के समर्थकों के खिलाफ ही नहीं था बल्कि आनेवाले वर्षों में औद्योगिक मजदूरों और कम्यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ भी इसने कार्यवाई की और लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमे चलाए गए और अंततः विरोधियों का सफाया करने वाले और आतंक मचाने वाले खुफिया पुलिस के खिलाफ भी यही कार्य किया गया।

1930 के दशक में स्टालिन की कम से कम तीन राजनैतिक जरूरतों की चर्चा इतिहासकारों ने की है। उन्होंने सबसे पहले साम्यवादी दल के भीतर उसकी नीतियों के खिलाफ उठने वाले विरोधी स्वरों और आलोचनाओं को दबाया। 1933-34 में इसी दबाव के कारण औद्योगीकरण और सामूहीकरण अभियान में ढील दी गई, मजदूरों को रियायत दी गई और पूर्व विरोधियों से समझौता किया गया। उनकी दूसरी जरूरत न केवल विरोधियों को परास्त करना था बल्कि सभी प्रकार के संभावित विरोधों को जड़ से उखाड़ फेंकना था और उन पर आक्रमण करने के साथ-साथ दलीय नेतृत्व की जनतांत्रिक परम्पराओं में निहित आलोचना के स्वर को समाप्त करना था। इसकी परिणति स्टालिन की तीसरी जरूरत के रूप में हुई जिसमें उन्होंने एकदलीय शासन व्यवस्था को एकशासक राज्य सत्ता में बदलने का प्रयास किया। अपने इस कार्य के समर्थन में स्टालिन केवल यही तर्क दिया करता था कि वह यह सब कुछ राज्य सत्ता के खिलाफ हो रहे षडयंत्र को रोकने के लिए कर रहा था। उसका कहना था कि इस षड्यंत्र में केवल दलीय संगठन ही नहीं बल्कि खुफिया पुलिस और सेना भी शामिल थी। बिगड़ती अन्तरराष्ट्रीय स्थिति और युद्ध का खतरा दिखाकर बताया गया कि शासन खतरे में था परंतु जिन लोगों को मारा गया उनमें से एक भी व्यक्ति को जासूस या षड्यंत्रकारी साबित नहीं किया गया।

29.5.1 चार मुकदमे

1936,1937 और 1938 में चार मुकदमे चलाए गए जो विरोधियों को समाप्त करने के सबसे नाटकीय उदाहरण थे।

1) अगस्त 1936 में 16 लोगों पर चलाए गए मुकदमे में अभियोगकर्ता विशिंस्की द्वारा कैमिनेव, जिनौविवे और अन्य लोगों पर ट्रौटस्की के साथ षडयंत्र कर राज्य सत्ता को उखाड़ने और स्टालिन तथा पोलितब्यूरो के अन्य सदस्यों को हटाने का आरोप लगाया गया। आरोपियों ने कथित रूप से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार किया और कुछ अन्य दक्षिणपंथियों पर आरोप लगाया। उन्हें गोली मार दी गई।

2) जनवरी 1937 को 17 लोगों पर चले मुकदमे में पियाताकोव, मोरालोव और रडेक जैसे लोगों पर जापान और जर्मनी से मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार किया और उन्हें भी मृत्यु दंड दिया गया।

3) लाल सेना को प्रभावी बनाने वाले मार्शल तूखाचेवेस्की और अन्य सेनाप्रमुखों ने इन मुकदमों की जमकर आलोचना की। मई 1937 में उन्हें और अन्य प्रमुख सेनाध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया और उन पर जर्मनी और जापान के साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया गया; उन्हें भी गोली मार दी गई।

4) मार्च 1938 में 21लोगों पर चले मुकदमे में बुखारिन, रीकोव और यागोडा भी शामिल थे। अभियोगकर्ताओं ने यह दावा किया कि विदेशी जासूसी एजेंसियां सोवियत रूस में बुर्जुआ पूंजीवादी राज्य सत्ता की स्थापना के लिए दक्षिणपंथी और ट्रॉटस्की के समर्थकों का एक दल निर्मित करना चाहती थीं और सोवियत रूस से गैर रूसी क्षेत्र को अलग कर देना चाहती थीं।

ये बस थोड़े से ही उदाहरण हैं। 1937 और 1938 के पूरे दो वर्षों में सरकार, दल, मजदूर और सेना और यहां तक कि पुलिस में काम करने वाले लोगों को जनता का शत्रु कहकर गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेलों और श्रमिक शिविरों में बंद कर दिया गया। स्टालिन के अलावा लेनिन के पोलित ब्यूरो के सभी सदस्यों पर या तो मुकदमा चलाकर मार दिया गया या दूसरे तरीकों से उनकी मृत्यु हो गई। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, साम्यवादी अन्तरराष्ट्रीय (कॉमिन्टर्न) के दो भूतपूर्व अध्यक्ष, मजदूर संगठन के प्रमुख और राजनैतिक पुलिस के दो अध्यक्षों को मृत्युदंड दिया गया।

29.5.2 परिशोधन और साम्यवादी दल

परिशोधन कार्यक्रम में राज्य द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को राज्य विरोधी कह कर हत्याएं की गईं जिन्हें राज्य ने परिशोधन का नाम दिया। इसका सबसे ज्यादा असर दल के भीतर हुआ। क्रांति के पहले भूमिगत रहकर, गृहयुद्ध और सामूहीकरण के युग तथा पंचवर्षीय योजना के दौरान पनपे साम्यवादी नेताओं के समूह को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 1941 में जब रूस ने द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा लिया तबतक रूसी क्रांति के नेतृत्व से उसके सारे सम्पर्क लगभग टूट चुके थे। इस प्रकार आतंक के राज्य ने पुराने साम्यवादी दल को नष्ट कर दिया जिसे बाद में ख्रुश्चेव के जमाने में ही फिर से गंभीरतापूर्वक गठित किया जा सका। पुराने साम्यवादी दल के नष्ट हो जाने से स्टालिन की दल, सरकार और देश पर पकड मजबूत हो गई।

29.5.3 परिशोधन और सेना

केवल दल ही ध्वस्त नहीं हुआ बल्कि सेना के बड़े अधिकारियों का भी परिशोधन कर दिया गया। व्यापक सफाया कार्यक्रम के अन्तर्गत सोवियत सेना के 35 से 50 प्रतिशत सेनाधिकारियों का सफाया कर दिया गया। सेनाध्यक्ष कार्यालय के जाने माने सदस्य जैसे मार्शल टुखासेवेस्की और ब्लेशर और जेनरल गमारनिक और यामिर को मार दिया गया। उसके अलावा सर्वोच्च युद्ध परिषद के सदस्यों, पांच में से तीन मार्शलों, सोलह में से चौदह सेनाध्यक्षों और सभी एडमिरलों की हत्या कर दी गई। जिला के सभी सेना प्रमुखों, रेजिमेंटल कमांडर में से आधे लोगों तथा एक को छोड़कर सभी फ्लीट कमांडरों को गोली मार दी गई।

इन सफाया कार्यक्रमों के चलते लाल सेना की देशभक्ति का अपमान हुआ और इससे सेना कमजोर हो गई। नाजियों के खिलाफ युद्ध करते समय जितने वरिष्ठ सेना अधिकारी नहीं मारे गए थे उससे ज्यादा इस सफाया कार्यक्रम के दौरान मारे गए।

29.5.4 परिशोधन और सोवियत समाज

1930 के दशक का आतंक घर-घर में प्रवेश कर गया और सोवियत जनता ने बहुत गहराई से इसे अनुभव किया। सब लोग इस बात से सहमत हैं कि 5 प्रतिशत लोगों को जेल में डाल दिया गया था; लगभग अस्सी लाख लोगों को बंदी बनाया गया था जिसमें 10 प्रतिशत लोगों की हत्या कर दी गई। 1938 तक लगभग हर घर से एक व्यक्ति जेल में बंद था। शिक्षित समुदायों में यह अनुपात और भी ज्यादा था।

1930 के दशक का आतंक सामूहीकरण से इस अर्थ में भिन्न था कि यह शहरी जनसंख्या, राजनैतिक नेताओं, सैनिक अधिकारियों तथा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्गों के खिलाफ था। लोगों को इसलिए दंड दिया गया क्योंकि उन पर शक था कि वे सोवियत समाज को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसका निर्धारण उनके सामाजिक वर्गीकरण, सामाजिक उत्पत्ति, राष्ट्रीयता या समूह सदस्यता के आधार पर किया गया। सामाजिक वर्गीकरण लोगों की नियति का आधार बन गया। यह बताना जरा मुश्किल है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को मार डाला गया क्योंकि ये आंकड़ें अभी भी फाइलों में बंद है। 1990 में सोवियत अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया कि 1931 और 1953 के बीच सरकारी ट्रिब्यूनल ने लगभग चालिस लाख को हिरासत में ले लिया जिनमें से [illegible] लोगों को मृत्यु दंड दिया गया परंतु बहुत लोगों की मौत दर्ज नहीं की गई और आंकड़ों में हेर-फेर किया गया, खो गए या नष्ट कर दिए गए। इसलिए ये संख्या निश्चित रूप से सत्य से बहुत दूर हैं और इनमे आकडो को बहुत कम करके बताया गया है।

बोध प्रश्न 3

1) इतिहासकारों के अनुसार 1930 के दशक मे स्टालिन की प्रमुख राजनैतिक प्राथमिकताएं क्या थी ? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

2) 1930 के दशक के [illegible] कार्यक्रम [illegible] साम्यवादी दल और सेना को किस प्रकार प्रभावित किया? पांच पंक्तियों में उत्तर दीजिए।

....

....

....

....

....

29.6 सारांश

इस इकाई में 1928 और 1941 के बीच की रूसी अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था के [illegible] पक्षों का विवेचन किया गया है: योजनाबद्ध औद्योगीकरण, कृषि का सामूहीकरण और 1930 के दशक का परिशोधन या संहार। योजनाबद्ध औद्योगीकरण के तहत पांच वर्षों के लिए औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया और व्यवस्थित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। कृषि के सामूहीकरण के द्वारा निजी खेतों को एक साथ मिला दिया गया और उन पर आधुनिक ढंग से राज्य के नियंत्रण में खेती की गई। दल के भीतर और बाहर स्टालिन की नीतियों का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ जो रूस की [illegible] शासन व्यवस्था को एकशासक राज्य व्यवस्था में परिवर्तित करना चाहता था, परिणामस्वरूप 1930 के दशक में विरोधियों का सफाया किया गया। इन सफाया कार्यक्रमों के तहत पुराने बोलशेविक, लेनिन के [illegible] ब्यूरो के सदस्यों, सेना के कई अधिकारियों और राज्य के कई अधिकारियों को मृत्युदंड दिया गया। वस्तुतः जिसने भी स्टालिन की नीतियों से अपनी असहमति जताई उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सामूहीकरण में निशाना ग्रामीण जनता को बनाया गया था जबकि 1930 के दशकों के सफाया कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहरी लोगों, सेना के उच्च अधिकारियों और राजनेताओं तथा शिक्षित जनता को निशाना बनाया गया था। यह कहा जा सकता है कि 1930 के दशक की सरकारी नीतियों के लिए रूसी समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी।

29.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) योजनाबद्ध उद्योग में औद्योगिक विकास की दिशा पूर्व निर्धारित होती है और पांच वर्षों के उत्पादन के लिए उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है। देखिए भाग 29.3

2) सोवियत रूस में कम समय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देखिए उपभाग 29.3.1, 29.3.2 और 29.3.3

बोध प्रश्न 2

1) नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत खेती योग्य जमीन जो कुलकों (अमीर किसान) के नियंत्रण में थी उसे सामूहिकों के नियंत्रण में ले लिया गया। अब खेती के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। देखिए भाग 29.4

2) हालांकि सभी वर्ग के किसानों ने सोवियत सरकार के सामूहीकरण अभियान का विरोध किया परंतु अमीर किसानों ने ज्यादा विरोध किया क्योंकि उनका नुकसान ज्यादा होना था। देखिए उपभाग 29.4.4

बोध प्रश्न 3

1) इस प्रश्न का उत्तर देते समय बताइए कि स्टालिन ने एकदलीय सत्ता से एक शासक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए किस प्रकार अपने सभी राजनैतिक विरोधों का सफाया कर दिया। देखिए भाग 29.5

2) परिशोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुराने साम्यवादी दल का और क्रांति के समय के सैनिक नेतृत्व वर्ग का सफाया कर दिया गया।

इस खंड के लिये कुछ उपयोगी पुस्तकें

हॉब्सबॉम, एरिक, *द ऐज ऑफ एम्पायर,* न्यू यार्क, 1987

जॉल, जेम्स, *यूरोप सिन्स 1870, ऐन इन्टरनेशनल हिस्ट्री,* पेंग्विन, 1976

शिरेर, विलियम, *राइस ऐंड फॉल ऑफ द थर्ड राईख,* ग्रीनविच, 1959

कार्र, ई.एच., *द रशियन रिवोल्यूशन फ्रॉम लेनिन टू स्टालिन: 1917-21,* लंदन

स्टिजपैट्रिक, शीला, *द रशियन रिवोल्यूशन,* ऑक्सफोर्ड, 1982

रॉबर्ट, जे.एम. *पेंग्विन हिस्ट्री ऑफ यूरोप*